



स्थायी सदस्यता पर भारत के दांवे

भारतीय प्रधानमंत्री ने अपना पूरा ध्यान आज की तारीख में विश्व के सामने मौजूद चुनौतियों और उन्हें हल करने के लिए जरूरी सुधारों पर केंद्रित रखा। उन्होंने कहा कि भारत इस तथ्य में गर्व का अनुभव करता है कि वह संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है।

नेहा शाह।।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं वार्षिक आमसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर भारत के दांवे की पुर्णवकालत की, साथ ही यह भी रेखांकित किया कि नई ताकतों को केंद्रीय भूमिका में लाए बिना दुनिया की यह सबसे बड़ी पंचायत खुद से की जाने वाली अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाएगी। उनका यह वक्तव्य क्रिया-प्रतिक्रिया के पचड़े में पड़े बगैर एक बड़े और जिम्मेदार राष्ट्र के प्रमुख की भूमिका और गरिमा के अनुरूप था। ध्यान देने की बात है कि उनसे थोड़ी ही देर पहले इसी मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रिकॉर्डेड भाषण हुआ था, जिसमें न केवल द्विपक्षीय मुद्दे उठाए गए बल्कि तरह-तरह

से भारत को निशाना बनाने की कोशिश भी की गई। यह न सिर्फ इस मौके का गलत इस्तेमाल था, बल्कि इसके पीछे भारत को उकसाने का इरादा भी जगजाहिर था।

इस बचकानी हरकत को नजरअंदाज करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने अपना पूरा ध्यान आज की तारीख में विश्व के सामने मौजूद चुनौतियों और उन्हें हल करने के लिए जरूरी सुधारों पर केंद्रित रखा। उन्होंने कहा कि भारत इस तथ्य में गर्व का अनुभव करता है कि वह संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। लेकिन इस संस्था की स्थापना के समय जो परिस्थितियां मौजूद थीं, वे अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। स्वाभाविक रूप से संयुक्त राष्ट्र का ढांचा भी पुराना पड़ गया है।



इसमें बदलाव की जरूरत बताते हुए प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के संचालन में भारत की ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका के सवाल को केंद्र में रखा। उन्होंने यह भी कहा कि वसुधैव कुटुंबकम् जैसे अपने जीवन मूल्यों के चलते भारत कभी विश्व शांति के लिए खतरा नहीं बनेगा। जब भी शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र की कोई पहल हुई, भारत ने उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और भारतीय सैनिक अपनी कुर्बानी देने में भी पीछे नहीं रहे। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बढ़ते संदेह और अविश्वास के मौजूदा माहौल में प्रधानमंत्री ने यह कहकर सभी संबंधित देशों को आश्वासन देने की कोशिश की कि जब भारत किसी एक देश से करीबी रिश्ता बनाता है तो इसका कतई यह अर्थ नहीं

होता कि वह किसी और देश के खिलाफ है। कोरोना महामारी की मौजूदा चुनौतियों के बरकस भी उन्होंने याद दिलाया कि कैसे भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाओं की सप्लाई की। वैक्सीन उत्पादन के क्षेत्र में भारत की विशाल क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने सदस्य देशों को भरोसा दिलाया कि भारत अपनी इस क्षमता का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल पूरी दुनिया से कोरोना वायरस का प्रकोप मिटाने में करेगा। बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का दो साल का कार्यकाल जल्द ही शुरू होने जा रहा है। उम्मीद की जाए कि इसी अवधि में इस परिषद की स्थायी सदस्यता का दायरा बढ़ाने संबंधी सुधार पर उपयुक्त फैसला लेकर उस पर अमल की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

कई कदम

अशोक वोहरा।

उन दिनों यह बहुत बड़ी रकम थी, जिसकी अदायगी के लिए शुजाउद्दौला की बेगम को अपने सारे बेशकीमती जेवर बेच देने पड़े। फिर भी हर्जाने की किरस्तें नवंबर, 1766 तक अदा की जाती रहीं। इस बीच लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड से नए गवर्नर जनरल बनकर आए तो वारेन हेस्टिंग्स से भी कई कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने बेबस शुजाउद्दौला का भयादोहन-सा करते हुए उनसे एक ऐसी संधि पर दस्तखत करा लिए, जिससे कड़ा व इलाहाबाद के इलाके उनके बजाय दिल्ली के बादशाह के हो गए। इतिहासकार इस संधि को 'इलाहाबाद की संधि' कहते हैं। इसके एक प्रावधान के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध में निर्बाध व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई तो दूसरे के तहत उसके नवाब के लिए कंपनी से दोस्ती लाजिमी हो गई।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

राष्ट्र के नाम संबोधन

प्रधानमंत्री नरसिंह राव पर सिर्फ विपक्ष ही हमलावर नहीं था, उनकी पार्टी में ही उनके खिलाफ मोर्चा खुल गया था। उन्होंने अपने सहयोगियों के दबाव में राष्ट्र को उसी रात संबोधित किया। अपने संबोधन में नरसिंह राव ने ध्वस्त इमारत को बार-बार बाबरी मस्जिद कहा। देश-विदेश में यह समझा गया कि ध्वस्त ढांचा मस्जिद था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह कहीं नहीं कहा कि उस इमारत में 44 साल से मूर्तियां रखी थी और वहां नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम प्रसारण से तनाव और बढ़ गया। समय बीतने के साथ कल्याण सिंह के हौसले धीरे-धीरे बुलंद हो रहे थे। वे पहले तो अचंभित थे, अपने को छला गया बता रहे थे, पर अब ढांचा गिरने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले चुके थे। इस्तीफे के बाद उनका दो टूक ऐलान था कि वह प्रबल हिंदू भावनाओं का विस्फोट था क्योंकि मामले को लटकाए रखने में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ही बराबर जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि यह सही है कि ढांचे की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैंने ली थी, लेकिन साथ-साथ मैंने यह भी कहा था कि मेरी सरकार संतों और कारसेवकों पर गोली नहीं चलाएगी। कल्याण सिंह ने बेलौस कहा, 'ढांचे से कारसेवकों को हटाने के लिए गोली न चलाने के लिए कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है। फाइलों पर मेरे दस्तखत हैं। जब मैंने रास्ता निकाला था, तब किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैं विवादित इमारत और कारसेवा की जगह को अलग करना चाहता था। मेरी योजना थी कि 2.77 एकड़ से विवादित ढांचे को अलग कर उस हिस्से में कारसेवा कराई जाए। ये सेप्टी वॉल्व था, उससे छह दिसंबर की घटना टाली जा सकती थी, पर मेरी बात नहीं सुनी गई, गैर बीजेपी दलों ने इसमें रुकावट डाली।

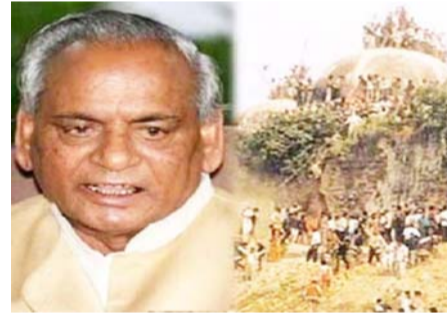
अयोध्या के कंट्रोल रूम से लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर तोड़फोड़ की सूचना दी गई तो मुख्यमंत्री अचंभित थे। कल्याण सिंह ने बिना गोली चलाए परिसर को खाली कराने को कहा, हालांकि वे इस बात से नाराज थे कि उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई।

गवर्नर से पीएम की नाराजगी

हेमंत शर्मा।।

जिस वक्त ढांचे पर कारसेवकों ने हल्ला बोला, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीति गर्म थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री सात, रेसकोर्स रोड के अपने घर पर टेलिविजन के सामने बैठे थे, तो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लखनऊ में कालिदास मार्ग के सरकारी आवास की छत पर धूप सेंक रहे थे। अयोध्या के कंट्रोल रूम से लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर तोड़फोड़ की सूचना दी गई तो मुख्यमंत्री अचंभित थे। कल्याण सिंह ने बिना गोली चलाए परिसर को खाली कराने को कहा, हालांकि वे इस बात से नाराज थे कि उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। अगर वीएचपी की ऐसी कोई योजना थी, तो उन्हें भी बताना चाहिए था। उधर अयोध्या में तोड़फोड़ जारी थी।

प्रधानमंत्री के निजी सचिव आरके प्रसाद ने भी फोन कर फैजाबाद के कमिश्नर से स्थिति नियंत्रित करने और केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करने को कहा। इसमें कोई शक नहीं कि ध्वंस के पहले पांच घंटे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपने साथ वैसे ही धोखा हुआ माना, जैसे प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने माना था। ध्वंस से जितने आहत नरसिंह राव थे, उतने ही आहत कल्याण सिंह भी लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें भ्रम में रखा गया। हालांकि कल्याण सिंह को कुछ-कुछ



अंदेशा था। शनिवार की रात जिला प्रशासन ने गृह सचिव को जो रिपोर्ट भेजी, उसमें कहा गया था कि कारसेवकों का एक वर्ग है जो कारसेवा का स्वरूप बदलने से नाराज है, यानी प्रतीकात्मक कारसेवा उसके गले नहीं उतर रही है।

मौके की नजाकत भांप कल्याण सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी को शनिवार की रात ही अयोध्या भेज दिया था। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक इन दोनों को रविवार की सुबह अयोध्या जाना था। ध्वंस के बाद शाम तक कल्याण सिंह सदमे से बाहर थे। उन्होंने लखनऊ में अपने आवास पर मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बड़े अफसरों की मीटिंग बुलाई। फाइल मंगा उस पर गोली न चलाने के लिखित आदेश दिए ताकि बाद में किसी अफसर की जवाबदेही

न तय हो। कल्याण सिंह के इस काम से नौकरशाही में उनकी साख बनी। अपने अफसरों और शीर्ष नेताओं से विमर्श के बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। कल्याण सिंह राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी से मिलकर इस्तीफा देना चाह रहे थे, पर राज्यपाल उन्हें मिलने का वक्त नहीं दे रहे थे क्योंकि राज्यपाल कल्याण सिंह से मिलने से पहले प्रधानमंत्री नरसिंह राव से बात कर लेना चाह रहे थे। शायद वे प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे थे कि कल्याण सिंह का इस्तीफा लेना है या उन्हें बर्खास्त करना है, पर नरसिंह राव ने राज्यपाल से बात करने से मना कर दिया। दरअसल नरसिंह राव राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी से इस बात से नाराज थे कि जब सारा देश कल्याण सिंह सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहा था, तो वे लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त न करने की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज रहे थे। नरसिंह राव को लगता था कि राज्यपाल ने भी उन्हें इस मामले में गुमराह किया है। अपनी अंतिम रिपोर्ट जो ध्वंस से दो रोज पहले राज्यपाल ने भेजी थी, उसमें यहां तक लिख दिया था कि अगर कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त किया गया तो ढांचे पर खतरा हो सकता है। ढांचा इसके गुस्से का शिकार हो सकता है। कल्याण सिंह बिना समय तय किए राजभवन पहुंच गए और उन्होंने शाम साढ़े पांच बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

सूडोकु नवताल-5489		****	
		कठिन	
5	3		
2	9 5		
9		6	
		3 5	
6		7	
4 8			
	7		3
	2 4	9	
	8	2	

सूडोकु नवताल-5489 का हल

4	2	5	8	6	1	9	7	3
7	3	1	9	4	2	8	5	6
6	9	8	7	3	5	4	2	1
1	6	2	3	8	9	5	4	7
9	4	3	5	1	7	6	8	2
8	5	7	4	2	6	3	1	9
2	1	9	6	5	8	7	3	4
5	7	4	1	9	3	2	6	8
3	8	6	2	7	4	1	9	5

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरने वाले आवश्यक हैं।
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में पूर्व 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक को पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
■ पहली का केवल एक ही हल है।

अपना ब्लॉग

कोई सरकारी सहायता नहीं

मोहन। राजस्थान में जैसलमेर के कठपुतली कलाकार ज्ञानी भाट की 80 वर्षीय माता शांति बाई बीमार हैं। बेहतर इलाज की उम्मीद में वह मां को जयपुर लाए थे। घर चलाने के लिए जयपुर के एक होटल में वह कठपुतली नचाने का काम करने लगे, पर लॉकडाउन में सब बंद हो गया। परिवार में मां समेत तीन छोटी लड़कियां, पत्नी और वृद्ध पिता हैं। इस समय उनके पास कोई सरकारी सहायता नहीं है। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान सरकार ने लोक कलाकारों को बचाने और उन्हें सहायता देने के नाम पर निहायत भद्दा मजाक किया है। एक योजना शुरू की गई 'मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना'। योजना का लाभ लेने वालों से कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोक कलाकार अपनी परफॉर्मिंग आर्ट्स का 15 से 20 मिनट का विडियो बनाकर हमें ईमेल करें। साथ में कहा गया कि सामाजिक दूरी का पालन होना चाहिए, जहां तक हो एकल व्यक्ति परफॉर्म करें।

